मानव संसाधन विकास मंत्री जी!

राष्ट्रपति भवन में आपकी जगह हो न हो इतिहास में आपकी जगह पक्की है

अभिनेत्री से नेत्री और फ़िर मंत्री बनी बैठी स्मृति इरानी के सितारे आजकल बुलंदी पर है। भविष्य में उनके सितारे उन्हें देश की राष्ट्रपति की गद्दी तक पहुंचायेंगे। उनके मंत्री बनने के घोषणा करने वाले राजस्थान के ज्योतिषी नत्थूलाल ने स्मृति इरानी के हाथ दिखाने पहुंचने पर यह भविष्यवाणी की।

स्मृति ईरानी का भविष्य भले ही बुलंदियों तक पहुंचे पर इस देश के बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है। जहां का शिक्षामंत्री अपने भविष्य के लिये ज्योतिषों के चक्कर काटे वहां शिक्षा की दुर्दशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे शिक्षा मंत्री के राज में पढने वाले बच्चे कितनी वैज्ञानिक सोच पर खड़े होंगे, इसे भी समझा जा सकता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद मैडम स्मृति ईरानी ने खासा नाम कमा लिया है। उनके मंत्रालय ने इतिहास के भगवाकरण के लिए इतिहास परिषद पर संघी मानसिकता का व्यक्ति बैठा डाला जो तथ्यों-सबूतों की परवाह किये बिना आर्यों को भारत का मूल निवासी बनाने को तत्पर है। आपके राज में दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग इतिहास का रिसर्च कर उन्हें संघ संमत बना रहा है। आपके आदेश से देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में निरामिष भोजन मिलना बंद हो गया है। आपके आदेश से अब सब केन्द्रीय विद्यालय में जर्मन की जगह भारतीय भाषा और विशेषकर संस्कृत पढाई जाने लगी है।

माननीया मंत्री जी आप जिस गति से संघ परिवार के एजेंडे पर काम कर रही हैं उससे देश के नौनिहालों का भविष्य अधिकाधिक अंधकार की ओर बढ रहा है। आप कहती हैं कि आपका ज्योतिषी को हाथ दिखलाना आपका व्यक्तिगत मामला है पर आपकी सहयोगी मंत्री नजमा हेपतुल्ला दो कदम आगे बढकर ज्योतिषी को विज्ञान ही घोषित कर डालती हैं। शायद आपका अगला कदम पाठ्यपुस्तकों में विज्ञान की जगह ज्योतिष की पुस्कतें शामिल करना होगा और फ़िर आप अपने प्रिय ज्योतिष नत्थूलाल को सीधे प्रोफ़ेसर डीग्री से सम्मानित करवा दें।

माननीया मंत्री जी जिस राज में हज़ारों लोगों के कत्लेआम के भागी मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हों, जहां एक सीरियल में भूमिका आपको मंत्री बनवा सकती हो वहां नत्थूलाल के प्रोफ़ेसर बनने पर कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। इस राज में आप राष्ट्रपति भी बन जायें तो कोई अजूबा नहीं होगा। और फ़िर ज्योतिष तो तर्क-विज्ञान को परे रख अजूबा करता ही रहता है।

माननीया मंत्री जी आपके नक्शेकदम की तार्किक परिणति इस ओर ले जाती है कि आप सारे स्कूल-कॉलेजों सें सभी विषय हटाकर इकलौता विषय ज्योतिष रखवा दें। बच्चे आये हाथ दिखलायें और पता लगा लें कि वे मज़दूर बनेंगे या पूंजीपति, मंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति। और फ़िर सरकार ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुरूप उन्हें तय काम दिलाने का जिम्मा संभाल ले। इस प्रोजेक्ट से शिक्षा के खर्च में भी भारी कमी होगी और समाज में ज्योतिषियों का मान-सम्मान भी काफ़ी बढ़ जायेगा। पक्का संघी रामराज की शिक्षा का खाका तैयार हो जायेगा।

पर मंत्री जी हर तुगलक को एक दिन गद्दी छोड़नी पड़ती है। इतिहास उनकी गद्दी के भय से नहीं बल्कि उनके कर्मों से उनकी इतिहास में जगह तय करता है। देश को राष्ट्रपति भवन में आपको जगह मिले न मिले पर इतिहास में आपकी जगह के बारे में पूरी विज्ञानसम्मत भविष्यवाणी की जा सकती है। इतिहास में आपकी जगह इतिहास की कूड़ेदान में होगी। अपने वक्त की पूरी पीढी के भविष्य को चौपट करने वाली शख्सियत के साथ इतिहास और जनता पूरा इंसाफ़ करेगी। इतना याद रखें कि देश टी.वी. सीरियल नहीं होता जहां डायरेक्टर मोदी के इशारे पर आपके अभिनय को जनता चुपचाप बर्दाश्त कर ले। जनता जब जागेगी तो डायरेक्टर-एक्ट्रेस सबका हिसाब चुकता करेगी।

-नागरिक

आवारा पशुओं से निजात दिलायेंगे विधायक विपुल?

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय भाजपा विधायक विपुल गोयल ने शहर की गलियों सड़कों पर आवारा घूमती गायों व कुत्तों से जनता को शीघ्र निजात दिलाने की घोषणा की है। यह 'शीघ्र' कितना शीघ्र होगा, समय ही बतायेगा।

सुधी पाठकों ने 'मज़दूर मोर्चा' के गतांकों में पढा होगा कि शहर भर के सरकारी अस्पतालों में 20 000 से अधिक लोग कुत्ता-काटे के टीके लगवाने आते हैं। सरकारी अस्पतालों में यह लागत 400-500 रुपये तक आती है। इन अस्पतालों में गरीब लोग ही आते हैं जिनके लिये यह रकम भी बहुत बड़ी होती है तथा जो दिहाड़ियां टूटती हैं वे अलग से। इसी तरह आवारा गायों व सांडों से जनता को जो परेशानी होती है सो होती है, पुलिस के लिये भी ये भारी सिरदर्दी का सबब बनी हुई हैं। शायद ही कोई रात खाली जाती होगी जब पुलिस और गौ-तस्करों के बीच मुठभेड़ न होती हो।

लगता है विधायक गोयल को आम जनता की यह मुसीबत समझ में आ गयी है। उक्त दोनों विषयों को गंभीरता से लेते हुए गोयल ने दिनांक 31 दिसम्बर को सेक्टर 16 स्थित अपने कार्यालय में गौ-पूजन के साथ घोषणा की कि अब शहर के सड़कों पर गायों को आवारा नहीं घूमने दिया जायेगा। तमाम लावारिस गायों को गौशाला भिजवा दिया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी गाय का मालिक होने का दावा जतायेगा तो उसे 5100 रुपये गौशाला में बतौर जुर्माना देकर छुड़ानी होगी। इसी तरह शहर भर में घूमते आवारा कुत्तों को भी किन्ही निश्चित स्थानों पर बन्द करके रखा जयेगा। इन दोनों कामों के लिये विधायक महोदय ने स्थानीय निकाय (नगर निगम) से सहयोग मांगा है।

सर्वविदित है कि किसी भी शहर में आवारा पशुओं को नियन्त्रित करना उस शहर के स्थानीय निकाय का महत्वपूर्ण कर्त्तव्य रहा है। किसी जमाने में इस शहर का स्थानीय निकाय भी अपना यह दायित्व बखूबी निभाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार व उसके अधिकारियों में बड़े पैमाने पर पनपे भ्रष्टाचार व हरामखोरी के चलते उन्होंने अपने इस दायित्व को बिल्कुल भुला दिया है। ऐसे में विपुल गोयल को इन लोग़ों से कोई सहयोग आसानी से सुलभ होने वाला नहीं है। इसके लिये उतनी ही सख्ती नगर निगम पर बरतने की जरूरत है जितनी किसी भी सरकारी काम को कराने के लिये जरूरी होती है।

जनता की इस मुसीबत को कम से कम एक सत्तारूढ विधायक ने तो समझा, यह प्रशंसनीय है। यदि तमाम विधायक तथा सांसद तमाम फ़िजूल के तमाशों उद्घाटनों व समापनों आदि को छोड़ कर जनता की मौलिक समस्याओं की ओर ध्यान दने लगें तो जनता को काफ़ी राहत मिल सकती है। उक्त घोषणा के 15 दिन बाद तक भी न तो कोई आवारा गाय और न ही कोई आवारा कुत्ता ही शहर की सड़कों गलियों से हटाय गया है। तमाम आवारा पशु ज्यों के त्यों सड़कों पर कायम हैं। इससे प्रतीत होता है कि विधायक महोदय केवल लफ़्फ़ाजी करने में ही माहिर हैं। उनकी असली रूचि तो केवल फिजूल के खेल तमाशों में ही बरकरार है। इसे सिद्ध करने के लिये उन्होंने 10 जनवरी को नाहर सिंह स्टेडियम में एक और क्रिकेट - तमाशा कर दिखाया।

भोपाल गैस त्रासदी के तीन दशक पूरे होने पर मोदी ने दिया देशवासियों को मौत का तोहफ़ा

देश में कम से कम 12 परमाणु संयंत्र लगाने के समझौते पर मोदी ने किये हस्ताक्षर

3 दिसम्बर 2014 को भोपाल गैस त्रासदी को तीन दशक पूरे हो चुके हैं। इस त्रासदी में हज़ारों लोग मारे गये और लाखों आज भी इस त्रासदी का दंश झेलने को मजबूर हैं। वहां की मिट्टी, हवा, पानी में आज भी जहरीले अंश मौजूद हैं। इस परमाणु विकरण के कारण वहां अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस त्रासदी के शिकार हज़ारों मृतकों के परिजन व पीड़ित और प्रभावित लोगों की आंखें न्याय की आस में पथरा गईं। आज भी भोपाल की जनता इस त्रासदी के दंश को झेल रही है। वहां की जमीन, हवा, पानी उस त्रासदी के जहर को अपने भीतर समाये हुए है। इस कांड के आरोपियों व कम्पनी को आज़ाद भारत की सरकारों ने कभी भी न्याय के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें भगाने में पूरी सुविधा और सहयोग दिया। राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह स्वयं उन्हें बड़ी शान के साथ विमान में बैठाने गये जैसे वह किसी हत्यारे, अपराधी की नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति की विदाई हो। मुख्य आरोपी एण्डरसेन को पिछले तीन दशकों में कभी भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका और जनता की उसको दण्डित करने की आशा उसकी मौत के बाद पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि एक भरा-पूरा जीवन जी कर वह इस दुनिया से विदा हो चुका है और इस भीषण हत्याकाण्ड के अन्य आरोपियों में से किसी को भी कोई सज़ा नहीं मिली। आज भी भोपाल सहित पूरे देश की जनता के सामने यह सवाल है कि क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने के लिये उन्हें सम्मानजनक मुआवजा भी मिल पायेगा। क्या भोपाल गैस त्रासदी के जैसे और हत्याकांड रचे जायेंगे या नहीं।

लेकिन पूंजीपतियों और उनकी सरकारों को इस बात की क्यों और कब चिंता होने लगी। उन्हें तो भरपूर मुनाफ़ा और डालर चाहिए। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने संसद में परमाणु विधेयक बिल पास कर करोड़ों जनता के स्वास्थ्य व जीवन की कीमत पर देशी-विदेशी पूंजीपतियों को अरबों-खरबों कमाने की छूट दी। वैसे पूंजीपति वर्ग के लिए मेहनतकश जनता की जान की कीमत कीड़े-मकोड़े से ज्यादा नहीं होती।

भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड एक विदेशी अमेरिकन कम्पनी थी, जिसे इस घटना के बाद डाव कैमिकल्स ने खरीद लिया है। और दोनों कम्पनियां उस दुर्घटना की हर जिम्मेदारी से बचना चाहती हैं।

यह विडम्बना है कि चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के बाद फुकुसिमास के परमाणु संयत्र से खतरनाक परमाणु विकरण के बाद जहां सारी दुनिया में ऊर्जा के इस रूप को अमान्य घोषित किया जा चुका है वहीं भारत सरकार ने इसे एक मौके के रूप में देखा है। फुकुसिमा के परमाणु संयत्र में हुई दुर्घटना के बाद भी भारत सरकार ने इससे कोई सबक नहीं लिया। यूकिको ताकाशाही जिसका घर फुकुसिमा में है, उसने भी भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परमाणु संयंत्र से होनेवाली दुर्घटना के संबंध में गम्भीर चिंता जाहिर की है। इस सबके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश से भारतीय मेहनतकशों के लिए मौत का तोहफ़ा खरीद लाये हैं और इस मौत को खरीदकर बहुत खुश भी हैं। रूस के साथ भारत सरकार ने 12 से अधिक नये परमाणु संयत्र लगाने व ऐसे ही 20 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें से एक कुडनाकुलम है।

लम्बे समय से कुडनाकुलम की जनता इस परमाणु संयत्र को बंद करने के लिये संघर्षरत है, जिसका भयंकर दमन किया जा रहा है। और आंदोलन में शामिल 5000 लोग़ों पर देशद्रोह का मुकदमा लाद दिया गया है, जो कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है और भोपाल गैस त्रासदी की बरसी 3 दिसम्बर के केवल एक सप्ताह बाद भी भारत के पूंजीपरस्त शासक वर्ग के नुमाइंदे नरेन्द्र मोदी ने पूंजीपतियों की पूंजी को और बढाने के बदले में करोड़ों भारतवासियों की जान को जोखिम में डाल कर रूस के साथ एक शर्मनाक समझौता किया है, जिसमें रूस 2035 तक भारत में कम से कम 12 परमाणु संयंत्र लगायेगा। इसके लिये उपकरण भी भारत में तैयार किये जायेंगे। परमाणु सहयोग पर रणनीतिक दृष्टि के दस्तावेजों में कहा गया है कि दोनों पक्षों के उन परमाणु बिजली घरों के तेजी से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। भोपाल गैस त्रासदी के तीन दशक बाद भारत के शासक वर्ग व उसके नुमाइंदों ने रूस के साथ देश में और परमाणु संयत्र लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर कर देश में अनगिनत हत्याकांड रचने का इंतज़ाम कर लिया है।

नागरिक

विश्व आर्थिक संकट, दक्षिणपंथी राजनीति और छात्र-नौजवान

-कमलेश

केन्द्र में भाजपा द्वारा सत्ता संभालने के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए संघी मंडली द्वारा दो साल से ध्रुवीकरण के लिए मुहिम जारी थी। भारतीय राजनीति अधिकाधिक दक्षिणपंथ की ओर झुकती जा रही है। भाजपा-नरेन्द मोदी का सत्तानशीन होना और भारतीय राजनीति का दक्षिणपंथ की ओर सरकना कारण नहीं परिणाम है। भारतीय राजनीति-सत्ता के दक्षिणपंथ की ओर सरकने के कहीं ज्यादा गहरे कारण हैं।

क्रांतिकारी राजनीतिक चिंतक दिमित्रोव ने कहा था कि 'आर्थिक व राजनीतिक संकट दोनो विद्यमान हों तो फ़ासीवादी विचारधारा शासक वर्ग पैदा कर लेता है।' दूसरे शब्दों में कहें तो 'फासीवाद का सम्बन्ध शासक वर्ग' के राजनीतिक-आर्थिक संकट में है।

दिमित्रोव के इस राजनीतिक विश्लेषण से यदि हम आज की दुनिया को देखें तो हम पाते हैं कि 2007 में आया विश्व आर्थिक संकट अभी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरी प्रेत आत्मा की तरह चिपका हुआ है। 2009-10 में कुछ सुधार की बात हुई किन्तु वह ज्यादा समय नहीं टिक सकी और 2011 से एक बार फ़िर अर्थव्यवस्थाएं लुढ़कने लगी। साम्राज्यवादी संस्थाएं व चिंतक संकट के चिरस्थाई होने तक की बातें करने लगे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के इस संकट ने पूंजीपतियों के मुनाफ़े के रथ पर ब्रेक लगा दिये हैं। पूंजीपति मुनाफ़े के लिए छटपटा रहे हैं। देशों की सरकारें संकट के जिम्मेदार पूंजीपतियों को तमाम छूटें-रियायतें देकर अर्थव्यवस्था को उभारने का प्रयास कर चुके हैं। किन्तु इससे भी बात नहीं बनी और संकट सरकारों व सरकारी कोष तक पहुंच गया। स्थिति सुधारने के बजाए और गंभीर हो गयी।

मुनाफ़ा कमाने के लिए छटपटा रहा पूंजीपति संकट से निकलने के रास्ते के तौर पर मज़दूरों के और भयानक शोषण की ओर बढ़ रहा है। उनके जीवन स्तर को गिराता जा रहा है। जिसके कुल परिणाम के बतौर समाज की क्रय शक्ति और कम होती जा रही है और पूंजीपति और गहरे आर्थिक-राजनीतिक संकट की ओर बढता जा रहा है। पूंजीपति अपने मुनाफ़ाखोर चरित्र के कारण इससे अलग और कुछ कर भी नहीं सकता।

वैश्विक स्तर पर हर देश में बेरोजगारों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। रोज़गार में लगे मेहनतकशों के वेतन में कटौती की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) से सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है। जिसके कुल परिणाम के बतौर मेहनतकशों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आती जा रही है। समाज में कंगालीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है।

समाज व जीवन के ये हालात मज़दूर-मेहनतकशों को संघर्ष के मैदान में लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। अरब देशों, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका के देशों के पिछले समय के प्रदर्शन इसी बात के गवाह हैं। मज़दूर-मेहनतकश, युवाओं के ये जोरदार प्रदर्शन लम्बे समय से सुस्त पड़ी दुनिया को हिला रहे हैं। इस खास बात के साथ-साथ इन प्रदर्शनों की भारी कमी यह है कि यह शासकवर्गीय दायरे तक ही सीमित हैं। ये प्रदर्शन मजबूत क्रांतिकारी विकल्प पैदा नहीं कर पाये हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रांतिकारी समाजवादी विकल्प के

शेष पेज छह पर